करने हेतु तैयार की गई है । परिकल्पित रोजगार दो किस्म के हैं:—स्वः रोजगार उद्यमों की स्थापना और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद लोक परिसंपत्तियों का सृजन करके मजदूरी रोजगार का प्रावधान । यद्यपि योजना का मुख्य लक्षित ग्रुप शहरी निर्धन हैं किन्तु महिला लाभानुग्राही तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभानुग्राही विशेष लक्षित ग्रुप हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

"राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड" का रुग्ण होना

1509. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1993 के "जनसत्ता" में "इस तरह डूबा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को रुग्ण घोषित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसे पिछले सात वर्षों से लगातार हो रहे घाटे के कारणों का पता लगा लिया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राष्ट्रीय परियोजना विकास लिमिटेड तुंगभद्रा परियोजना और इंदिरा सागर पावर हाउस के ठेके प्राप्त नहीं कर पाया, यद्यपि इसकी निविदा दर अन्य निविदाओं की दरों की तुलना में न्यूनतम थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि नेशनल प्रोजेक्टस कंसट्रक्शन कारपोरेशन उत्पादक यूनिट, न होने के कारण, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता है, फिर भी उक्त अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उसे रुग्ण यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ग) कम्पनी को वर्ष 1989–90 से हानि हो रही है । ऐसी स्थिति के मुख्य कारण ये हैं—ऊपरी खर्चों पर अनुपात हीन उच्च व्यय, भारी ब्याज बोझ, कार्य करने में विलंब तथा कुछ कार्यों पर एन०पी०सी०सी० द्वारा उद्धृत की गई दरें गैर-मितव्ययी पाई गई हैं ।

(घ) और (ङ) तुंगभद्रा परियोजना के लिये डाक के जरिये भेजे गये एन० पी०सी०सी० के टेंडर पर परियोजना प्राधिकरणों द्वारा विचार नहीं किया जा सका क्योंकि यह देरी से प्राप्त हुआ था । यद्यपि इंदिरा सागर परियोजना के विद्युतघर कार्यों के लिये एन०पी० सी०सी० का पहला टेंडर न्यूनतम था, लेकिन परियोजना प्राधिकरणों ने नये टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय किया है । इस बार एन०पी०सी०सी० टेंडर न्यूनतम नहीं था ।

Subansiri and Dihand Dam River Valley Projects

1510. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Brahmaputra Board and the Ministry